



2026:AHC-LKO:41117-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 5748 / 2026

राहुल गुप्ता

.... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: सुयश गुप्ता, सतीश चंद्र कशिष, येशी श्रीवास्तव
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. इस याचिका में उत्प्रेषण रिट जारी करके दिनांक 18.05.2026 की उस प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखण्डित करने की मांग की गई है, जो कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, गोंडा में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 323, 504 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं 191(2), 115(2), 352 के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 0442/2026 के रूप में दर्ज की गई थी।
2. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना और संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री को देखा। याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के समान हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष तक की सजा हो सकती है और पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 जिसमें धारा 35(3) से 35(6) तक शामिल हैं, के अंतर्गत बताए गए ढंग और प्रक्रिया का पालन करेगी। ऐसी स्थिति में, जांच अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

4. यह बताना उचित होगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के समान प्रावधान, अर्थात् धारा 41-ए को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अ र्शे कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273** वाद में निम्नलिखित टिप्पणी की थी।

5. हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष सुना है। **अ र्शे कुमार** वाद (उपर्युक्त) में निम्नलिखित (प्रासंगिक भाग) कहा गया है:-

"9. एक और प्रावधान, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए, जिसका उद्देश्य अभियुक्त की अनावश्यक गिरफ्तारी या गिरफ्तारी के डर को रोकना है, उसे प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। धारा 41ए, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 के माध्यम से जोड़ा गया था और जो इस मामले में प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"41ए. पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने का नोटिस -

(1) जिन वादों में धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जिसके विरुद्ध कोई उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी मिली है, या उचित संदेह है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है। इस नोटिस में उसे पुलिस अधिकारी के सामने या नोटिस में बताई गई किसी अन्य जगह पर पेश होने का निर्देश दिया जाएगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

(3) यदि वह व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और पालन करता रहता है, तो उसे नोटिस में बताए गए अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर यह राय न बनाए कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) यदि वह व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है, तो पुलिस अधिकारी सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, उसे नोटिस में बताए गए अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।"

"उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जिन वादों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को एक निर्धारित स्थान और समय पर अपने सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करे। विधि ऐसे अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह भी कहता है कि यदि ऐसा अभियुक्त नोटिस की शर्तों का पालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ पुलिस अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर यह मानता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस स्तर पर भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तारी के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा उसी तरह जांच की जाएगी जैसा कि पहले बताया गया है।"

6. उपरोक्त बातों और याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के बयान को ध्यान में रखते हुए जिसमें कहा गया है कि राज्य के अधिवक्ता के रुख को देखते हुए याचिका का निस्तारण किया जा सकता है और माननीय उच्चतम न्यायालय के **अर्नेश कुमार(उपर्युक्त)** वाद जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है और जिसका संबंधित भाग भी ऊपर दिया गया है, में दिए गए निर्णय की टिप्पणियों को देखते हुए, इस याचिका का निस्तारण किया जाता है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करें। इस धारा में गिरफ्तारी के लिए विधि, ढंग और प्रक्रिया बताई गई है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रावधानों के समान हैं, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्नेश कुमार(उपर्युक्त) वाद में स्पष्ट किया था।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

(न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

15 जून, 2026

अरविन्द/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।